>

Title: Regarding Kendriya Vidyalaya, Ghazipur, Uttar Pradesh.

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर): महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर अफीम फैक्ट्री की भूमि में स्थापित है। और आज तक वहीं पर है। 1986 से अफीम फैक्टरी के अंदर ही केन्द्रीय विद्यालय चल रहा है। चूंकि स्पांसर अफीम फैक्टरी है, केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में यह प्रचलन में है। जहां यह विद्यालय खुला है, उसका स्पांसर वहां अफीम फैक्टरी है। अफीम फैक्टरी राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, उसकी तरफ से लगभग पांच से छः साल पूर्व एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था और राजस्व विभाग की तरफ से मानव संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन की ओर भेजा गया था। लेकिन इन पांच-छः सालों के अंदर सिर्फ पत्रावलियों पर टीका-टिप्पणी हो रही है, जो समझ से परे है। गाजीपुर पूर्वांचल का एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां शिक्षा के नाम पर न कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है और न शिक्षा का कोई समुचित प्रबंध है। ऐसे जिले में जहां एक लम्बे समय से केन्द्रीय विद्यालय स्थापित है, जबकि कई जिलों में उसका अभाव है। लेकिन इतना अच्छा अवसर मिलने के बावजूद भी आज वहां 12वीं तक की शिक्षा मान्यता प्राप्त है, जबकि कक्ष वहां मात्र दस हैं। वहां पढ़ाई केवल दसवीं तक होती है, 12वीं तक पढ़ाई भी नहीं हो पाती है।

सभापति महोदय : आप चाहते हैं कि वह नये स्थान पर बने।

श्री राधे मोहन सिंह : सर, मैं उसी पर आ रहा हूं। वहां हालत यह है चूंकि अफीम फैक्टरी ने उसे जगह मुहैया करायी है, इसलिए उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह बहुत जर्जर अवस्था में हैं और उसमें बहुत सीलन भी है। उसे देखकर लगता है कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां आज की तारीख में 427 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। यह प्रस्ताव अब तक स्वीकृत हो गया होता, हालांकि वहां जमीन अफीम फैक्टरी के पास है, लेकिन पत्रावलियों में राजस्व विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच की कार्य पद्धति पर दुख हो रहा है और मुझे इनकी कार्य पद्धति और संस्कृति समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार न तो उस जमीन की नौइयत बदलनी है और न जमीन की दिशा बदलनी है।

महोदय, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि वित्त मंत्रालय ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 तक इस विद्यालय को बनाकर कम्पलीट किया जाए, इसके लिए धन भी आवंटित हो चुका है। मैं पूछ रहा हूं कि जब तक राजस्व विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जमीन ट्रंसफर नहीं करेगा, फिर 2015 तक इसका निर्माण कैसे हो सकता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने कई पत्र भी लिखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी पत्र का मुझे उत्तर नहीं मिल पाया।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी यह आप ही के विभाग से संबंधित मामला है।

श्री पबन सिंह घाटोवार : नहीं।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी का भी तो केन्द्रीय विद्यालय का मामला था।

श्री पबन सिंह घाटोवार : मैं पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : तब तो आप सर्वव्यापी हो गये। You may please note down. It is very important.

श्री राधे मोहन सिंह : सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जबकि केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार बिल 2010 पारित किया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी बोली से समझ रहा हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है और आपकी व्यथा को भी मैं समझता हूं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को इशारा किया है कि आप उसकी महता को समझें।

श्री राधे मोहन सिंह : सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, यह विषय कई बार यहां उठा है। वह विद्यालय बहुत जर्जर स्थिति में है, जबकि केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार बिल 2010 पारित किया है।

सभापति महोदय : श्री संजीव गणेश नाइक आप बोलिये।

श्री राधे मोहन सिंह : मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा मैंने यहां उठाया है कि यदि वहां सब कुछ ठीक है, फिर विलम्ब के कारण क्या हैं, विलम्ब के लिए दोषी कौन हैं और इस दोष के साथ-साथ उसे तत्काल शुरू कराने का कष्ट करे और माननीय मंत्री जी से जो आपने कहा है उसका आश्वासन चाहता हूं।, यही मेरी विनती है।

सभापति महोदय : मैंने स्वयं कह दिया है।